(SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) On 28 May, 1990, India proposed a Package of Confidence Building Measures to Pakistan. Pursuant to this, five rounds of Foreign Secretary level talks have been held so far. Another round of these talks is proposed to be held soon.

(c) These talks have covered the entire gemut of bilateral issues between the two countries.

हुकुम चन्द मिल लिमिटेड, इंदौर का बंद किया जाना

@*276. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अचानक बंद कर दी जाने वाली किसी भी टेक्सटाइल मिल के मजदूरों को केंद्रीय सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है;

(ख) क्या यह सच है कि इंदौर स्थित हुकुम चन्द मिल लिमिटेड को बी० आई० एफ० आर० द्वारा परिसमापन के आदेश जारी कर दिये जाने पर अचानक बंद कर दिया गया है और यदि हां, तो उस मिल के मजदूरों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(ग) केन्द्रीय सरकार मिल को क्या सहायता प्रदान कर रही है;

(घ) क्या यह भी सच है कि मिल के प्रवर्तक गायब हैं और मिल के मजदूरों को उन्हें देय राशियों का भुगतान नहीं हो रहा है; और

(ङ) क्या टेक्सटाइल मजदूरों को राष्ट्रीय कपड़ा निधि से भुगतान किया जाएगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) से (ङ) वर्ष 1985 की वस्त्र नीति के अनुसरण में उन मिलों के कामगारों के लाभ के लिए वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना की स्थापना की गई है जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25(ओ) के अंतर्गत औपचारिक रूप से बन्द की गई हैं अथवा एकक को समाप्त करने की प्रक्रिया के दौरान कंपनी अधिनियम, 1976 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा एक सरकारी परिसमापक की नियुक्ति की गई है। औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ० आर०) ने 11 सितम्बर, 1991 को मैसर्स हुकुम चंद मिल्स, इंदौर को समाप्त करने का निर्णय लिया था क्योंकि उसके लिए पुनर्स्थापना पैकेज व्यावहारिक नहीं पाया गया था। उसके बाद बैंकों ने बैंकिंग प्रचालन बंद कर दिया और सूचना के अनुसार 9 दिसम्बर, 1991 से मिल को बन्द कर दिया गया। मिल ने औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण संबंधी अपील प्राधिकारी (ए०ए०आई० एफ०आर०) को एक अपील दायर की है। इस समय यह मिल वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना के अंतर्गत राहत पाने की पात्र नहीं है क्योंकि न तो यह औपचारिक रूप से बंद की गई है और न ही सरकारी परिसमापक की नियुक्ति की गई है।

राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार निजी प्रबंधक इन्दौर से अदृश्य हो गए हैं। तथापि, श्रम न्यायालय के आदेश पर कामगारों को मिल के तैयार माल की बिक्री के बाद नवंबर, 1991 तक के वेतन अदा कर दिए गए हैं।

तथापि, सरकार ने किसी राष्ट्रीय वस्त्र निधि की स्थापना नहीं की है।

@पूर्वतः तारांकित प्रश्न 236, 12 मार्च, 1992 से स्थानान्तरित।

Setting up of Karnataka High Court bench at Dharwad

*277. SHRI H. HANUMANTHAPPA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to establish a Bench of the Karnataka High Court at Dharwad; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI K. VIJAY BHASKARA REDDY): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन न किया जाना

*278. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जून, 1991 में तत्कालीन वस्त्र मंत्री द्वारा राष्ट्रीय वस्त्र निगम, भारतीय कपास निगम, राष्ट्रीय हथकरघा निगम और वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के कार्यों की जांच करने और इनके कार्यों में सुधार करने हेतु सुझाव देने के लिए कुछ समितियां गठित की थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन

आदेशों का पालन नहीं किया गया है और इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) से (ग) तत्कालीन वस्त्र मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, ए०ई०पी०सी० तथा एन०टी०सी० के क्रियाकलापों की जांच करने के लिए अलग-अलग समितियां स्थापित की जाएं। तथापि, चुनाव प्रक्रिया चलने के कारण इन तीन समितियों की स्थापना के संबंध में औपचारिक आदेश जारी नहीं किए जा सके।

Killing of Indian Fisherman

*279. SHRI K.K. VEERAPPAN:
SHRI V. GOPALSAMY: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an Indian fisherman from Tamil Nadu was killed by the Sri Lankan Navy on 10th February, 92; and

(b) what is the number of Indian fishermen who were injured in firing and what action Government of India have taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) Government have seen a Press report regarding the alleged incident on 10 February 1992. However, this has not been corroborated by our Naval and Coast Guard authorities.

राज्यों की योजना को अंतिम रूप दिया जाना

*280. **श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) विभिन्न राज्यों ने परामर्श के बाद अपनी-अपनी योजनाओं को किस प्रकार से अंतिम रूप प्रदान किया है;

(ख) राज्यों ने अपने-अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों को क्या-क्या निदेश जारी किए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) राज्य योजना परिव्यय उपाध्यक्ष योजना आयोग तथा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के बीच विचार-विमर्श के आधार पर तय किये जाते हैं। बाद में क्षेत्रकीय आवंटन पारस्परिक परामर्श से तय किए जाते हैं। स्कीमों के लिए वास्तविक प्रावधान राज्य सरकारों द्वारा अपने संबंधित राज्य बजटों में किए जाते है।

(ख) राज्य सरकारों के अपने योजना संसाधनों को बढ़ाने के प्रयास में ये शामिल है:—व्यय में किफायत कर तथा गैर-कर राजस्व बढ़ाने के उपाय तथा राज्य स्तरीय उद्यमों से अतिरिक्त संसाधन जुटाना।

(ग) राज्य सरकारों को संसाधन अनुमानों के बारे में विस्तृत मार्गदर्शी निर्देश जारी किए गये तथा मार्गदर्शी निर्देशों एवं उनके साथ वित्तीय संसाधन संबंधी विचार विमर्शों के दौरान दोनों में अतिरिक्त संसाधन जुटाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

Iran's Proposal for Regional security

2709. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Iran has sought regional security with the help of our country in the wake of disintegration of the Soviet Union;, and

(b) if so, what are the details thereof and the Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI MADHAVSINH SOLANKI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

New Political treaty with Russian Federation

2710. DR. SANJAYA SINGH: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to have a new political treaty with the Russian Federation; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI MADHAVSINH SOLANKI): (a) Yes, Sir. The Government of the Russian Federation has proposed that an Agreement on Friendship and Cooperation between India and the Russian Federation be signed.

(b) The proposed Agreement is still under negotiation. Specific points to be included in it will be defined only after it is finalised.